Consumption of fertilizers

1489. SHRI SARADA MOHANTY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the quantum of different kinds of fertilizers consumed by various States annually during the last three years;

(b) the agencies/organisations involved in the distribution and sale of fertilizers; and

(c) the steps taken to increase the consumption of fertilizers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) A statement indicating the quantum of different fertilizer nutrients consumed by States during the years 1991-92, 1992-93 and 1993-94 is at Annexure. [*See* Appendix 172, Annexure No. 34]

(b) The State institutional agencies namely, the State Co-operatives, the State Agro-Industries Corporations, the State Marketting Federation etc., the public sector organisations and private agencies are involved in the distribution and sale of fertilizers.

(c) The Government of India has taken the following steps to increase the consumption of fertilisers in the country :—

(i) concession of Rs. 1000 per tonne each on Muriate of Potash (MOP) and indigenous Di-Ammonium Phosphate (DAP), proportionate per tonne concession on indigenous complexes and Rs. 340 per tonne on SSP is being given during 1994-95.

(ii) sale of fertilisers to farmers in small bags;

(iii) free soil testing service to farmers;

(iv) a scheme on balanced use of fertilisers is being implemented which is expected to help in generating demand and promoting balanced use of fertilisers; and

(v) a scheme on Bio-fertiliser production and promotion is being implemented. This is expected to help in supply and use of organic forms of plant nutrients.

Creation of Central body for Agricultural Export Promotion

1490. DR. NAUNIHAL SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering the creation of a Central body for agricultural export promotion and identification of competitive products for processing and exports; if so, what is the latest position and details thereof; and

(b) what are details of the present directions of such exports and the projected directions for the coming years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) No, Sir.

(b) Major agricultural products like deoiled cakes, cashew, tobacco, spices, rice, wheat, fruits and vegetables etc. are being exported to the countries in West Asia, South East Asia, U.S.A. and Europe and the posibilities of their exports to Israel and South Africa are being explored.

Production of cotton

1491. SHRI RAHASBIHARI BARIK : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the total area under cotton cultivation in the country;

(b) whether Government have a proposal to increase the areas under cotton cultivation during the Eighth and Ninth Plan periods;

(c) if so, the additional areas identified for the purpose;

(d) whether Government propose to grow cotton in the non-traditional areas too; and

(e) if so, the plan drawn up thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) The total area under cotton cultivation in the country is around 75 lakh hectare.

(b) No, Sir.

(c) Question does not arise.

(d) There is no specific proposal as yet to grow cotton in the non-traditional areas.

(e) Question does not arise.

कृषक एसोसिएशन का गठन

1492. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1992 में त्वरित कृषि विकास हेतु किसानों अनुसंधान संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य पक्षों के सहयोग से एक लघु कृषक एसोसिएसन गठित करने का निर्णय लिया था :

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1994 तक सरकार

द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं : और

(ग) यह एसोसिएशन कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस कृष्ण कुमार) . (क) से (ग) "लघु कृषक एसोसिएशन" (एस. एफ. ए. सी.) को कृषि मंत्रालय द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 1994 को सहकारी समिति पंजीयन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत कराया जा चुका है ।

राज्यों के बीज निगमों की संरचना में परिवर्तन करना

1493. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :**
श्री आस मोहम्मद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों के बीज निगम के ढांचे को परिवर्तित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) मार्च, 1990 में 236.01 करोड़ रुपयों की कुल लागत पर राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण III शुरू किया गया था जिसमें विश्व बैंक की 150 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता शामिल है जो इस समय के रुपये डालर समानता मूल्य के अनुसार 405.00 करोड़ रुपये बैठती है । इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(i) किसानों को समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की उपयुक्त किस्मों की उचित दामों पर उपलब्धता सुनिश्चित करा कर उनकी सहायता करना ।

(ii) राष्ट्रीय तथा/राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के बीज निगमों की कार्यक्षमता में सुधार लाना ताकि उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके; और

(iii) पर्याप्त संस्थागत वित्त के द्वारा निजी बीज क्षेत्र के उद्योगों के संवर्धन के लिये सुविधायें उपलब्ध कराना ।

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जैसे 12 सहभागी राज्यों के राज्य बीज निगम भी इस परियोजना के लाभान्वितों हैं । तकनीकी परामर्शदाताओं द्वारा प्रबंध समीक्षा अध्ययनों पर आधारित अनुमोदित सहमत कार्ययोजना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम, हैदराबाद और गुजरात राज्य बीज निगम, गांधीनगर (गुजरात) के साम्या ढांचों में बेहतर वित्तीय क्षमता के लिये परिवर्तन किया गया है । गुजरात के मामले में निगम को शेयर पूंजी ढांचे को निम्न प्रकार की पद्धति अपनाने का सुझाव दिया गया है :—

(क) गुजरात सरकार—60 प्रतिशत
(ख) उत्पादक/सहकारी समितियों/डीलर —20 प्रतिशत
(ग) भारत सरकार—20 प्रतिशत

आन्ध्र प्रदेश के मामले में निगम का पूंजीगत ढांचा इस प्रकार है :—

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार—35 प्रतिशत
(ख) राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार—35 प्रतिशत
(ग) बीज उत्पादक— 35 प्रतिशत

पूंजीगत ढांचे में किये गये इन परिवर्तनों को अतिरिक्त निगम को उनके कार्यात्मक विभागों की अध्यक्षता के लिये व्यवसायिक व्यक्तियों को रखने की भी सलाह दी गई है ।

Farmers' Agitation in Punjab

1494. SHRI RAM JETHMALANI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state whether the Central Government are aware of the farmers' agitation in Punjab based on the lack of storage space at various markets and the failure of the farmers to dispose of their agricultural products at reasonable prices ?